पत्रिकायन

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। -वाल्तेयर

सारा जगत स्वतंत्रता के लिए लालायित रहता है, फिर भी प्रत्येक जीव अपने बंधनों को प्यार करता है।
अरविंद घोष

पोलमपोल
भायो

- नेताजी का फोन मैं
- रहग्यौ कय्याँ छेद
- लंका बँटाढार छै
- द्यै घर का जद भेद

सियासी जासूसी

गंभीर से गंभीर मुद्दों को महज राजनीतिक कारणों से हल्के में लेने का नतीजा देश पहले भी भुगत चुका है और यही हाल रहा, तो आगे भी भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता अरुण जेटली के फोन टेप हुए या नहीं, हुए तो सरकार ने किए या निजी जासूसों ने, या फिर बात सिर्फ कॉल डाटा रिकॉर्ड को खंगालने की रही हो। तीन महीने में तो जांच होकर सच सामने आ जाना चाहिए था। सूत्रों के हवाले से राजनीतिक गलियारों में फैल रही खबरों पर यकीन किया जाए, तो जेटली के फोन की टेपिंग या काल डिटेल खंगालने की बात लम्बे समय से चल रही है। चार लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। देश के गृह मंत्री का इस मामले पर संसद में बयान भी आ गया। राजनीतिक आरोपों-प्रत्यारोपों का सिलसिला भी परवान पर है। इन सबके बावजूद देश को अब तक यह पता नहीं कि असल माजरा क्या है? राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता का फोन टेप हो रहा है या नहीं, इसकी जांच एक महीने में पूरी क्यों नहीं हो सकती? और सवाल सिर्फ जेटली या उन जैसे चंद नेताओं या कुछ उद्योगपतियों का भी नहीं है। सवाल यह है कि जेटली के फोन टेपिंग मामले में पकड़ा गया अनुराग सिंह पहले अमर सिंह फोन टेपिंग मामले में भी गिरफ्तार हो चुका है। मामले की जांच तब भी हुई थी, बयान भी आए, लेकिन खुलासा कुछ नहीं हुआ। उसी अनुराग सिंह का जेटली मामले में गिरफ्तार होना यह दर्शाता है कि मामला ठंडा पड़ा नहीं कि पुलिस सो जाती है आंख मूंदकर। अगर ऐसा नहीं तो उसी अनुराग सिंह का साहस कैसे हो गया, फिर जासूसी करने का। साफ है, फोन टेपिंग के खेल में जुड़े खिलाड़ियों को न पुलिस का डर है और न कानून का।

मामला गंभीर है, लिहाजा सरकार यह कहकर बरी नहीं हो सकती, यह भाजपा का अंदरूनी मामला है। अगर जेटली के फोन टेप के पीछे भाजपा के ही लोग हैं, तो भी यह सरकार का कर्त्तव्य बनता है कि वह जासूसों का नाम सामने लाए। ताकि पता तो चल सके कि जेटली के फोन भाजपा का कौन नेता क्यों टेप करा रहा था। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि और कितने नेताओं, नौकरशाहों और उद्योगपतियों के फोन टेपिंग या कॉल डिटेल निकलवाए जा रहे हैं। अब तक इस मामले से गंभीरतापूर्वक निपटने की तैयारी सरकार ने भले न दिखाई हो, लेकिन अब पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसी जासूसी केवल निजता में दखल ही नहीं, बल्कि आपराधिक किस्म का काम है।

सम्पादकीय

सरकार को सक्रिय होना पड़ेगा। भाजपा नेताओं के फोन टेप का मामला देश के सामने पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए।

महासमर (1750)

प्रच्छन्न : कुंती

यह कर्ण के चरित्र तथा कृत्यों का जन सामान्य द्वारा किया गया मूल्यांकन है... दुर्योधन से मिल कर जो कुछ वह कर रहा है, उसके प्रति अपनी वितृष्णा प्रकट करने के लिए लोक मानस ने इस रूप में कर्ण के चरित्र को यह दर्पण दिखाया है।...'

कुंती के मन पर एक अनाम-सा अवसाद घिर आया, 'शायद तुम ठीक कह रहे हो विदुर!'

इस चर्चा में कुंती का और मन नहीं लगा।... ऐसा क्यों है कि कर्ण अपनी भूल समझ नहीं पा रहा? क्यों वह पतन के गर्त में गिरता जा रहा है? क्यों वह पांडवों से घृणा करता है? क्यों वह कृष्णा का विरोधी है? वह उस दुर्योधन से कैसे प्रेम कर सकता है, जिसमें प्रेम करने योग्य कुछ भी नहीं है?

कुंती को जैसे रात भर नींद नहीं आई। जो थोड़ी देर वह सोई भी, उसे लगता रहा कि वह सो नहीं रही, कठिन श्रम का कोई बहुत जटिल काम कर रही है। एक अनन्त यात्रा, अनवरत यात्रा...। वह यात्रा भी बड़ी विचित्र थी। उसके पास न कोई अश्व था, न कोई रथ; किंतु वह निरंतर गतिशील थी। वह समझ नहीं पाई कि जब न उसके पास कोई वाहन था और न ही वह चल रही थी, तो वह गतिशील कैसे थी। उसे जैसे इच्छागति का कोई वरदान मिल गया था। उसका मन जहां, जिस ओर जाना चाहता था, वह उसी ओर प्रवाहित हो जाती थी, जैसे मनुष्य का शरीर न हो, पवन का कोई झकोरा हो।...

वह उन स्थानों पर घूम रही थी, जिन्हें वह पहचानती भी नहीं थी। वहां वह पहले कभी नहीं गई थी। फिर भी वह वहां इस प्रकार आ-जा रही थी, जैसे उस सारे क्षेत्र का उसे पूरा ज्ञान हो। उसके साथ मार्गदर्शक कोई नहीं था; किंतु फिर भी वह बिना किसी असुविधा के अपना मार्ग खोज लेती थी। और फिर कुंती ने देखा कि वह हिमालय के किसी बहुत ऊंचे शृंग पर पहुंच गई है। स्थान बहुत ही पवित्र है, बहुत सात्विक। वहां पहुंचकर जैसे मनुष्य के मन का सारा मल कहीं तिरोहित हो जाता है। उसके मन में कोई कलुष रह ही नहीं पाता। कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं। मन भी जैसे पारदर्शी धवल हिम का ही एक अंग हो जाता है।... उसी स्थान का एक हिमखंड सहसा पिघलने लगा। वह जल पहले तो कुछ दूर तक एक ही धारा के रूप में बहता रहा; किंतु फिर एक शिलाखंड से टकराकर वह अनेक धाराओं में बंट गया।...

क्रमशः नरेन्द्र कोहली

पाठक पीठ

करे कोई, भरे कोई

पुनः परीक्षा परिणाम का दर्द। आरपीएससी द्वारा गत वर्ष से जो भी परिणाम जारी किए जा रहे हैं, वे सभी विवादग्रस्त रहे। एक ही परीक्षा के कई बार परीक्षा परिणाम जारी करना क्या परीक्षा प्रणाली की वैधता तथा विश्वसनीयता के लिए उचित है? न्यायपालिका के समक्ष जब भी आरपीएससी अपने कर्तव्य निर्वाह में असफल सिद्ध हुई, आरपीएससी के अधिकारी को सजा नहीं दी गई। सजा सुनाई गई बेरोजगार, कमजोर अभ्यर्थियों को पुनः परिणाम जारी करने के आदेश देकर। लगता है जैसे आरपीएससी के द्वारा कई बार परीक्षा परिणाम जारी करने की प्रथा बन गई है। न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा लोक सेवा आयोग के बीच पिस रहे अभ्यर्थियों का दर्द कौन सुनेगा?
कृष्णा शर्मा, जयपुर

सही पाठ्यक्रम

व्याकरण भाषा का अनुशासन है, लेकिन एनसीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम में इसका कोई नामोनिशान ही नहीं है। कक्षा दसवीं, ग्यारहवीं एवं बारहवीं की शिक्षा ज्ञानार्जन का उच्च सोपान है, जहां विद्यार्थी भाषा, साहित्य, नीति और जीवन की सुंदर, सरस झांकियों का दर्शन करता है। लेकिन वर्तमान पाठ्यक्रम ने तो इसकी परिभाषाएं ही समाप्त कर दी हैं। विलोम और पर्यायवाची से लेकर छंद, रस, अलंकार और भाषा तथा साहित्य इतिहास का मैदान खाली पड़ा है। पाठ्यक्रम निर्माताओं की सोच क्या रही है? इस पर शिक्षा विभाग को पुनर्विचार कर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं तथा अन्य विषयों की सुदृढ़ बुनियाद देने के लिए पाठ्यक्रम परिवर्तन का कदम उठाना चाहिए।
दिव्यराज 'दिनेश', जोधपुर

किसके काम का ये बजट

संसद में बजट पेश हो चुका है, मगर पारित होने में अभी थोड़ा समय बाकी है। इस बजट में आखिर किसको फायदा मिला? जानने के लिए हमने विशेषज्ञों से तो राय मांगी ही, साथ में जनता का मन भी टटोला। सैम्पल सर्वे के तहत हमने देश के 23 शहरों के कुल 230 लोगों से सवाल पूछे। सवाल, जिनसे साफ हो सके कि आम बजट में जनता से जुड़ी चिंताओं को समुचित स्थान दिया गया या नहीं। तस्वीर ये सामने आई कि न तो जनता खुश है और न ही विशेषज्ञ बजट को फायदेमंद मानते हैं।

1 क्या इस बजट से आप संतुष्ट हैं?

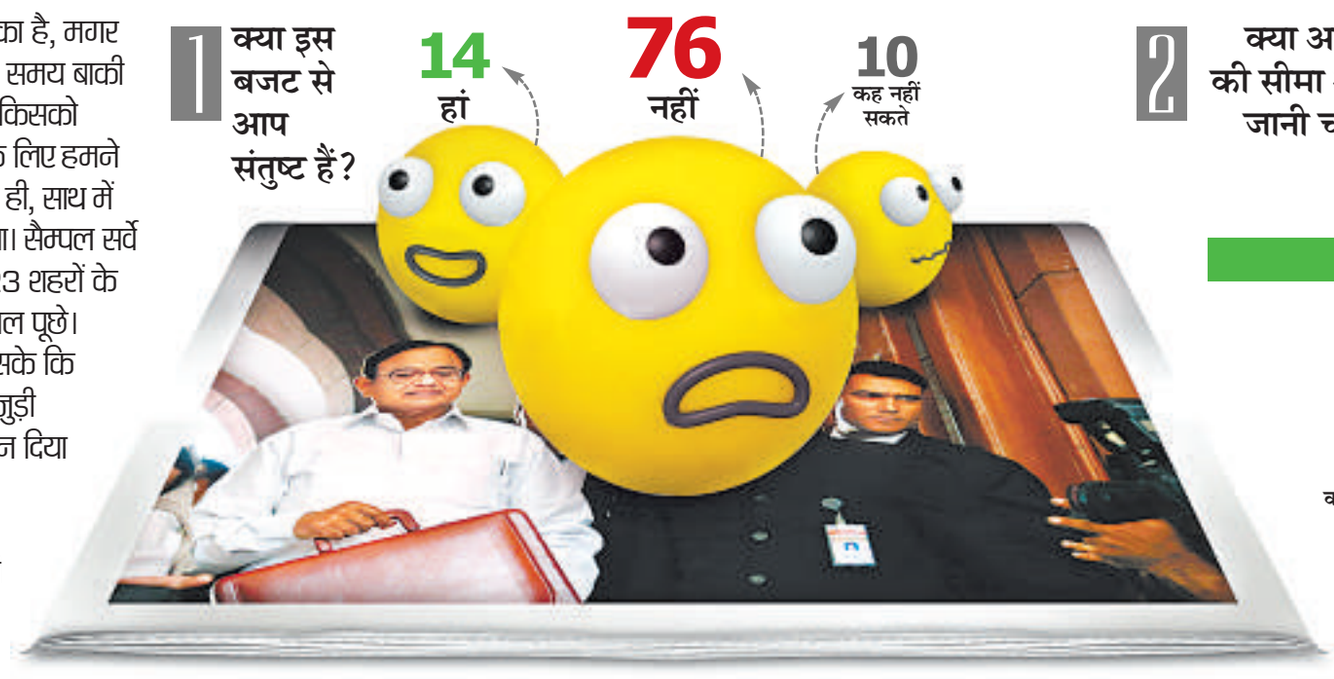

14 हां | 76 नहीं | 10 कह नहीं सकते

2 क्या आयकर छूट की सीमा और बढ़ाई जानी चाहिए थी?

90 हां | 07 नहीं | 03 कह नहीं सकते

सभी आंकड़े प्रतिशत में

3 क्या ये बजट महंगाई को रोकने की गारंटी देता है?

8 हां | 74 नहीं | 18 कह नहीं सकते

महंगाई बढ़ाएगा ये बजट

यह बजट आने वाले दिनों में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाएगा। केवल राजनीतिक घोषणाएं बजट में की गई हैं जिनसे आम आदमी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। समझ में नहीं आ रहा है कि चिदंबरम आखिर करना क्या चाहते हैं? पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सिडी कम होने से डीजल महंगा होगा, सीधा असर आम वस्तुओं पर पड़ेगा। किसानों को भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अच्छा होता कि चिदंबरम अच्छी और अर्थनीति वाली राजनीति करते। जनता चाहती है कि रोजगार मिले, महंगाई कम हो। इसके प्रयास होने जरूरी हैं।
परंजॉय गुहा ठाकुरता, आर्थिक मामलों के जानकार

4 क्या ये बजट बेरोजगारी दूर करने की गारंटी देता है?

9 हां | 78 नहीं | 13 कह नहीं सकते

निवेश नहीं तो रोजगार कैसे

यह बजट बिल्कुल बेरोजगारी को दूर करने की गारंटी नहीं देता। संकलन की राशि लगातार घटती जा रही है और चालू खाता घाटा, वित्तीय घाटा और राजस्व घाटा बढ़ रहा है। बजट में निवेश के लिए जो पूंजी शेष रहती है, उससे ही विकास दर बढ़ती है और रोजगार सृजन होता है। जब निवेश के लिए सारे बजट का महज छह प्रतिशत से कम ही उपलब्ध हो,रोजगार सृजन कहां होगा? बजट में दक्षता विकास की बात कही गई है, जब पहले से ही जो दक्ष लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो नए लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा?
सोमपाल शास्त्री, पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री

5 क्या बजट आंतरिक खतरों से बचाने की गारंटी देता है?

12 हां | 64 नहीं | 24 कह नहीं सकते

सरकार को दिखानी होगी इच्छाशक्ति

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने गृहमंत्रालय के बजट में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर अच्छा फैसला किया है, लेकिन केवल बजट बढ़ाने से आतंकवाद और नक्सलवाद के खतरों से नहीं बचा जा सकता है। इसके लिए सरकार को ऐसी नीति बनानी पड़ेगी जिसका असर जमीन पर दिखाई दे। पिछली बार भी इस सरकार ने कई घोषणाएं की, लेकिन उन्हें अमल में नहीं लाया गया। घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए इच्छाशक्ति जरूरी है। सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी होगी जिन पर तुरंत अमल किया जा सके।
अजीत डोभाल, पूर्व आईबी चीफ

6 क्या ये बजट महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देता है?

34 हां | 46 नहीं | 20 कह नहीं सकते

नहीं दे सकता महिला सुरक्षा की गारंटी

यह बजट क्या कोई भी एक बजट महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। मुझे नहीं लगता है कि निर्भया फंड या महिला बैंक से महिला सुरक्षा की गारंटी दी जा सकती है। क्या महिला बैंक खोल देने से महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी के लिए जरूरी है कि लोगों का उनके प्रति रवैया बदले। सरकार को इस पर काम करना चाहिए। आज ही दिल्ली में एक बलात्कार हो गया। महिला सुरक्षा तो एक ऐसा विषय है, जिस पर सरकार को लगातार काम करते रहना चाहिए।
डॉ. अल्पना कटेजा, एचओडी, अर्थशास्त्र, राजस्थान विवि

7 क्या ये बजट निवेशकों का पैसा बढ़ाने की गारंटी देता है?

32 हां | 40 नहीं | 28 कह नहीं सकते

निवेशकों में नहीं जगा पाए भरोसा

वित्त मंत्री के बजट भाषण में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे निवेशकों में विश्वास पैदा हो। अभी वित्तीय घाटा कम करने की जरूरत है। इसके लिए राजस्व बढ़ाए जाने और खर्चे कम करने की बात होनी चाहिए थी। लेकिन पब्लिक एक्सपेंडीचर कम नहीं किया है। एक तरफ निवेश प्रोत्साहन के उपायों पर चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ कॉरपोरेट इनकम पर टैक्स बढ़ाने और अमीरों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाने की बात कही है। पहले से लागू टैक्स लॉ को लेकर पिछले साल बहुत चर्चा हुई थी उस पर वित्त मंत्री ने कुछनहीं कहा।
राजीव कुमार, फिक्की के पूर्व महासचिव

8 क्या ये बजट देश को विकास की ओर ले जाएगा?

27 हां | 45 नहीं | 28 कह नहीं सकते

विकास से ज्यादा वोटबैंक की फिक्र

यह बजट निवेश बढ़ाने की कोई गारंटी नहीं देता है। सरकार ने निवेश के लिहाज से जो योजनाएं बनाई हैं, उनका क्रियान्वयन हो तो 3-4 साल में कुछ फर्क देखने को मिल सकता है। सरकार के पास इतने आयस्रोत ही नहीं हैं कि वित्तीय घाटे को कम किया जा सके। पावर और आधारभूत संरचना क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहित करना चाहिए था। इक्विटी मार्केट के लिहाज से भी कोई बेहतर प्लान नहीं है। आम आदमी के लिए कोई खास फायदेमंद बजट नहीं है। गरीबों को भी फायदा तभी होगा, जब ये पैसा उन तक पहुंचे।
धवल पी व्यास, चीफ मार्केट एनालिस्ट

नेता मिलकर राह निकालें

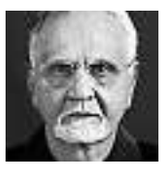

राजेन्द्र शेखर
सीबीआई के पूर्व निदेशक

देश की अखंडता और आम जन की सुरक्षा ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर राजनीतिक स्वार्थ कतई हावी नहीं होना चाहिए। और, दुर्भाग्यवश, आतंकवाद की मार अधिकतम आम जन पर ही पड़ती है। राजनीतिक पैंतरेबाजी अतिघातक भी हो सकती है, यह श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या ने सिद्ध कर दिया। ज्ञानी जैल सिंह को इंदिरा गांधी ने 1980 में गृह मंत्री नियुक्त किया ख़ास कर इसलिए कि वे पंजाब में अकालियों के विरोध में एक प्रतिकूल तबका खड़ा करने में उनका सहयोग करें। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल नाकामयाबियों से भरपूर रहा, जिसमें खालिस्तान रूपी अलगाववाद का पुख्ता होना सबसे अहम था। मैं उन दिनों सीबीआई में उप-महानिरीक्षक के पद पर आतंकवाद सम्बंधी मुकदमों की देखरेख में कार्यरत था। इसी दौरान 24 अप्रेल 1980 को निरंकारी बाबा की दिल्ली में हत्या हुई और यह कयास था कि धर्मगुरु संत भिंडरावाले इस काण्ड के प्रणेता थे, क्योंकि उससे पहले उनके पंथ और निरंकारियों में कई झड़पें हो चुकी थीं। हत्या के बाद दिल्ली में धारा 144 (दंड प्रक्रिया संहिता) लागू कर दी गई, जिसके तहत पांच या उससे ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर मनाही थी। इसके बावजूद भिंडरावाले के हथियारबंद दल को दिल्ली में गृह मंत्रालय के आदेश के अंतर्गत बेरोकटोक आने दिया गया। आदि से अंत तक मामला इतना बिगड़ा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरावाले का अंत हुआ, जिसकी दुखद इति इंदिरा गांधी की हत्या में हुई।

बहरहाल, ज्ञानी जैल सिंह के गृह मंत्री कार्यकाल के दो साल नकारात्मक असफलता से परिपूर्ण रहे व उसके पुरस्कार स्वरूप उन्हें राष्ट्रपति के ओहदे से सुशोभित कर दिया गया, जिस पद को उन्होंने बड़े आदर भाव से यह कहकर स्वीकार किया, 'यदि मेरी नेता मुझसे झाड़ू लगाने के लिए भी कहतीं, तो मैं ऐसा करता।' हमारे वर्तमान गृह मंत्री भी जहां तक चरम राजभक्ति का सवाल है, कुछ ऐसी ही मिट्टी के बने दिखते हैं। जब एक प्रख्यात टी वी पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या उनको इस पद पर इसलिए ही बैठाया गया है कि वे आंख बंद कर 10 जनपथ के निर्देशों का पालन करेंगे, तो उनका बेहिचक जवाब था, 'मैं आज जो कुछ भी हूं, वह सोनिया जी की बदौलत हूं। वो मुझसे जो कुछ भी कहेंगी, मैं करूंगा।' अतः उन्हें बेढंगी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने की और नाकामियों से लैस होने के लिए ढाल मिल गई है, ऐसा प्रतीत होता है। तभी तो वे दुष्कर्म विरोधी रैली के सदस्यों को माओवादियों की संज्ञा देने में नहीं कतराए। जब उनसे पूछा गया कि वे फ़ौरन हैदराबाद क्यों नहीं गए, तो वे बोले, 'मैं रात भर टी वी देखता रहा।' क्या इस जवाब को तुरंत घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायज़ा न लेने की माकूल प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? कांग्रेस के चिंतन शिविर के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भगवा (हिन्दू) आतंकवाद का अड्डा बता दिया और बाद में उतनी ही बेफिक्री से अपने इलज़ाम वापस ले लिए। निष्क्रियता का एक चिरपरिचित बहाना है, जो उन्होंने अख्तियार किया है, वह यह कि एनसीटीसी (राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र) का गठन हो जाता, तो हमें आतंकवाद रोकने का एक कारगर औजार मिल जाता। इशारा है, विपक्ष का इस संस्था के खिलाफ प्रतिरोध। शिंदे की इन युक्तियों के परिपेक्ष्य में क्या वे आशा कर सकते हैं कि विपक्ष और अन्य राज्य, खासकर भाजपा शासित राज्य, एनसीटीसी के गठन की स्वीकृति दे देंगे?

आतंकवाद बनाम राजनीति : यदि देश आतंकवाद से निजात पाना चाहता है, तो उसके नेताओं को ऐसे मसलों पर राजनीति से बाज आना पड़ेगा। केवल देशहित देखना पड़ेगा।

इस सन्दर्भ में अजीत डोभाल, पूर्व आईबी (केन्द्रीय खुफिया ब्यूरो) निदेशक का एक अंग्रेज़ी दैनिक में लेख महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि 2007 के बाद आतंकी हमलों की पुनरावृत्ति से कई सौ जानें गई हैं और दुःख की बात यह है कि आतंक के राजनीतिकरण ने इस खतरे से लड़ने की ताक़त को केवल कमजोर ही किया है। उन्होंने तीन ख़ास बातों पर जोर दिया है। एक - आतंकवाद को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए। दो यह कि एनसीटीसी (राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र) स्थापित होने में देर न हो और तीसरा यह कि अमरीका में 9/11 काण्ड के बाद एनसीटीसी आतंकी कहर की रोकथाम में बहुत कारगर सिद्ध हुई है। देखा जाए, तो ये तीनों मुद्दे एक दूजे पर निर्भर हैं। मैं सर्वप्रथम अमरीका के इस क़ानून और हमारे प्रस्तावित क़ानून की रूपरेखा की ओर ध्यान आकर्षित करना मुनासिब समझता हूं। उस देश की एनसीटीसी खुफिया विभाग के तहत होते हुए भी स्वायत्त है। और उसका कार्य अन्य खुफिया एजेंसियों की सूचनाओं को एकत्रित कर आकलन करना और विभिन्न एजेसियों में समन्वय स्थापित करना है। जबकि हमारी प्रस्तावित एनसीटीसी गृह मंत्रालय की मातहती में आईबी के माध्यम से काम करेगी तथा सूचना एकत्रित करने के अलावा इस संस्था को अनुसंधान, तलाशी, गिरफ्तारी करने का अधिकार भी सौंपने का इरादा है। केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों को भरोसा दिलाना होगा कि राज्यों के अधिकार में हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं है और यह तभी हो सकता है, जब अनुसंधान आदि का कार्य राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी (एन आई ए)/ सीबीआई पर छोड़ दिया जाए, संघीय अपराधों में इन एजेंसियों को क्षेत्राधिकार की बंदिश के बिना कार्य करने की (एफबीआई की तरह) अनुमति दी जाए। मूलतः बीच का रास्ता निकाला जाए, जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे।

अमरीका की मिसाल हम लेते हैं, तो यह समझना ज़रूरी है कि उस देश की अक्षुणता को पक्ष व विपक्ष ने सर्वोपरि रखकर आतंकवाद की चुनौती का संयुक्त रूप से सामना करने की ठानी। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हर किसी समस्या को हमारे नेता राजनीतिक स्वार्थ से आंकते हैं और एक दूसरे पर दोष मढ़ने की पैंतरेबाजी में मशगूल हो जाते हैं और इच्छाशक्ति की कमी के कारण सरकार देशहित में भी कोई कठोर कदम नहीं उठा पाती है। समय आ गया है कि बयानबाजी को तिलांजली देकर एकजुट होकर समस्या का समाधान किया जाए। हालांकि भाजपा नेता वेंकैया नायडु के कथित अभिशाप, गृह मंत्री जहन्नुम में जाएं, से समझौते की डगर और भी कांटों भरी हो गई है।